

1 गगनयान: मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन

- भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन।
- लक्ष्य: निकट पृथ्वी कक्षा (LEO) में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना और सुरक्षित वापसी।
- मानव-रेटेड LVM3 लॉन्च वाहन का उपयोग।
- कू मॉड्यूल, जीवन-समर्थन व रिकवरी प्रणाली शामिल।
- इसरो द्वारा पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से विकसित।
- रणनीतिक स्वायत्तता और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को मजबूती।
- अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा।



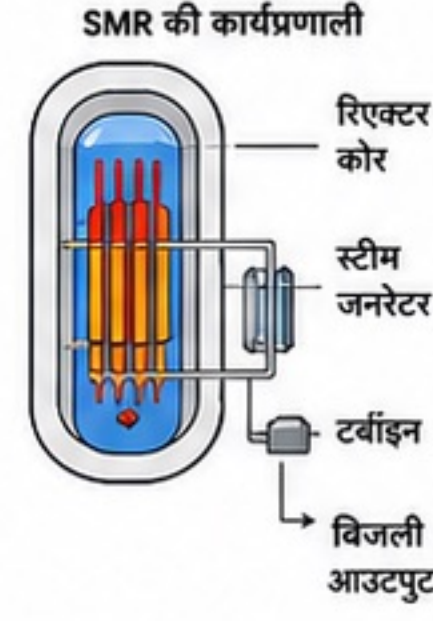
गगनयान के प्रमुख घटक

मूल्य संवर्धन: ~400 किमी कक्षा | मिशन अवधि ~3 दिन
भारत की रणनीतिक क्षमता, प्रौद्योगिकी और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन।

कीवर्ड: इसरो, LEO, LVM3, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

2 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)

- भारत 'भारत SMR' (BSMR) कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है।
- SMR आमतौर पर <300 मेगावाट विजली उत्पादन करते हैं।
- कम लागत, मॉड्यूलर निर्माण और तेज स्थापना।
- उन्नत सुरक्षा विशेषताएँ।
- दूरस्थ क्षेत्रों व औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त।
- स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका।
- नेट जीरो 2070 लक्ष्य के अनुरूप।



SMR की कार्यप्रणाली

मूल्य संवर्धन: भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम का पूरक; स्वच्छ, विश्वसनीय और सतत ऊर्जा सुरक्षा।

कीवर्ड: परमाणु ऊर्जा, SMR, BSMR, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा

3 राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NNFM)

- रासायनिक-मुक्त एवं सतत कृषि को बढ़ावा।
- जहामृत, बीजामृत, मल्लिङ और मिश्रित फसल प्रणाली का उपयोग।
- मिट्टी की सेहत और जल धारण क्षमता में सुधार।
- किसानों की लागत में कमी।
- जैव विविधता और कार्बन संचयन को बढ़ावा।
- जलवायु-रेजिलिएंट कृषि पद्धति।
- SDG 2 (भूखमरी शून्य) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) से संबंधित।



प्राकृतिक खेती की चक्रीय प्रक्रिया

मूल्य संवर्धन: अन्नदाताओं की आय वृद्धि, मूदा स्वास्थ्य सुधार और टिकाऊ कृषि आजीविका।

कीवर्ड: सतत कृषि, मूदा स्वास्थ्य, जैव इनपुट, SDGs

4 डीप ओशन मिशन

- भारत का प्रमुख 'ब्लू इकोनॉमी' मिशन।
- गहरे समुद्र के संसाधन, ऊर्जा और जैव विविधता की खोज।
- 6 प्रमुख घटक: पनदुब्बी, गहरे समुद्र खनन, जलवायु सेवाएँ, समुद्री जैव विविधता, समुद्री ऊर्जा, समुद्री जीव विज्ञान।
- महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में सहायक।
- समुद्री विज्ञान, संरक्षण और सुरक्षा क्षमता को मजबूत करता है।
- SDG 14 (जलमग जीवन) से जुड़ा।
- भारत की समुद्री शक्ति और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा।



6 प्रमुख घटक

मूल्य संवर्धन: ब्लू इकोनॉमी का प्रमुख चालक; सामरिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ।

कीवर्ड: ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधन, UNCLOS, सतत विकास

5 राष्ट्रीय क्वांटम मिशन

- 2023 में अनुमोदित; क्वांटम प्रौद्योगिकी का स्वदेशी इकोसिस्टम विकसित करना।
- 4 फोकस क्षेत्र: क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसर और सामग्री।
- रक्षा, साइबर सुरक्षा, दवा खोज, वित्त और मौसम पूर्वानुमान में उपयोग।
- स्टार्टअप और उद्योग-शोध सहयोग पर जोर।
- भारत को क्वांटम शक्ति राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
- उच्च कौशल, नवाचार और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।



क्वांटम प्रौद्योगिकी के उपयोग

मूल्य संवर्धन: भविष्य की उद्योगों, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी में भारत को वैश्विक नेतृत्व का अवसर।

कीवर्ड: क्वांटम कंप्यूटिंग, नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकी, रणनीतिक बढ़त

6 स्कूलों में AI व डिजिटल शिक्षा

- पाठ्यक्रम में AI साक्षरता, कोडिंग और भविष्य कौशल पर फोकस।
- AI और डिजिटल लर्निंग हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित।
- डिजिटल कक्षाएँ और शिक्षक प्रशिक्षण का विस्तार।
- PM SHRI, DIKSHA, SWAYAM, NDEAR जैसी पहल से जुड़ा।
- शिक्षा में डिजिटल विभाजन कम करने का प्रयास।
- युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना।



AI शिक्षा पारिस्थितिकी

मूल्य संवर्धन: मानव पूंजी सशक्ति, नवाचार क्षमता और डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन।

कीवर्ड: AI साक्षरता, डिजिटल इंडिया, शिक्षा सुधार, कौशल विकास

7 सीमा-पार पेपरलेस व्यापार ढांचा

- FTP 2023 के तहत इन्वेंटरी-आधारित क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क अनुमोदित।
- डिजिटल दस्तावेजीकरण और वेयरहाउस एकीकरण।
- तेज कस्टम्स क्लियरेंस और कम लेन-देन लागत।
- MSME निर्यातकों के लिए लाभकारी।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायक।
- 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' को बल।
- व्यापार सुगमता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार।



पेपरलेस व्यापार प्रक्रिया

मूल्य संवर्धन: MSME निर्यात को बढ़ावा, व्यापार लागत में कमी और वैल्यू चेन में दक्षता।

कीवर्ड: FTP 2023, ई-कॉमर्स, व्यापार सुविधा, लॉजिस्टिक्स

8 वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी का अधिकार मान्यता प्राप्त।
- व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों का कानूनी संरक्षण।
- आवास, चराई, लघु वनोपज, जल स्रोतों पर अधिकार।
- ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका।
- जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा।
- सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को प्रोत्साहन।



FRA के प्रमुख अधिकार

मूल्य संवर्धन: आदिवासी सशक्तिकरण, संरक्षण और सहभागी शासन के बीच संतुलन स्थापित करता है।

कीवर्ड: FRA, जनजातीय अधिकार, ग्राम सभा, सामाजिक न्याय

9 भारत के EV इकोसिस्टम का रोडमैप

- EV विनिर्माण और अपनाने को लिए समग्र रोडमैप जारी।
- प्रमुख पहल: PM E-DRIVE, FAME, PLI (ACC बैटरी), बैटरी निर्माण।
- चार्जिंग अवसंरचना और बैटरी इकोसिस्टम पर फोकस।
- आयात निर्भरता और उत्सर्जन में कमी।
- हरित विनिर्माण, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा।
- नेट जीरो 2070 लक्ष्य के अनुरूप।



EV इकोसिस्टम के स्तंभ

मूल्य संवर्धन: ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम।

कीवर्ड: EV, हरित गतिशीलता, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई

अन्य महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2025 जारी - राज्यों की राजकोषीय प्रबंधन गुणवत्ता का आकलन।

दक्षिणी पाकिस्तानी घाटों में वर्षा का हाथियों की आवाजाही पर प्रमुख प्रभाव - नई अध्ययन रिपोर्ट।

SC ने नागरिकता पर निष्पक्ष व कानूनी प्रक्रियाओं पर जोर दिया; अनुचित नागरिकता निरस्तीकरण पर रोक की बात।

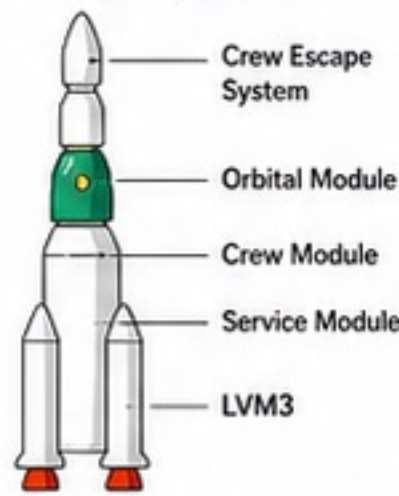
भारत-जापान रक्षा संबंधों की समीक्षा; 2+2 संवाद की तैयारी तेज़ करने पर सहमति।

नाभिकीय अपशिष्ट जल के फिल्ट्रेशन हेतु कुशल विधि विकसित।

1 Gaganyaan: Human Spaceflight Mission

- India's first indigenous human spaceflight mission by ISRO.
- Aims to send astronauts to Low Earth Orbit (~400 km).
- Mission duration ~3 days.
- Uses human-rated LVM3 launch vehicle.
- Includes crew module, life-support & recovery systems.
- Boosts strategic autonomy & space economy.
- Strengthens India's global space stature.

Gaganyaan Mission Components



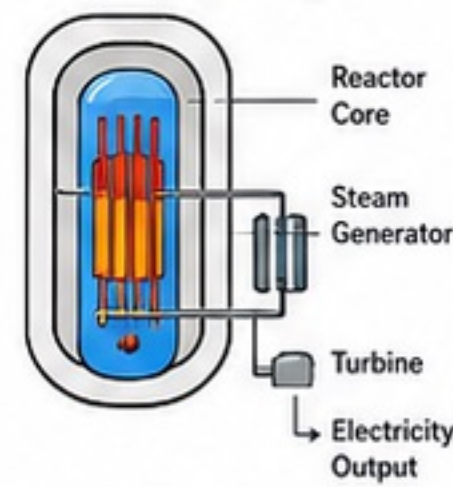
Value Addition: Opens door for future missions – space station, lunar missions, commercial spaceflight.

Keywords: ISRO, LEO, LVM3, Space Economy

2 Small Modular Reactors (SMRs)

- India promoting Bharat Small Modular Reactors (BSMRs).
- SMRs produce <300 MW electricity.
- Lower capital cost & modular construction.
- Enhanced safety & faster deployment.
- Suitable for remote areas & industrial use.
- Supports India's clean energy transition.
- Aligned with Net Zero 2070 goal.

SMR Working



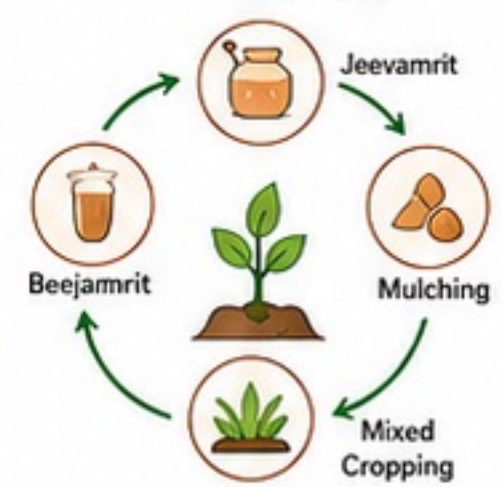
Value Addition: Complements India's 3-stage nuclear programme & energy security goals.

Keywords: Nuclear Energy, Clean Power, BSMR, Sustainability

3 National Natural Farming Mission (NNFM)

- Promotes chemical-free & sustainable agriculture.
- Uses Jeevamrit, Beejamrit, mulching & mixed cropping.
- Improves soil health & water retention.
- Reduces input cost for farmers.
- Enhances biodiversity & carbon sequestration.
- Supports climate-resilient agriculture.
- Aligned with SDG 2 & SDG 13.

Natural Farming Cycle



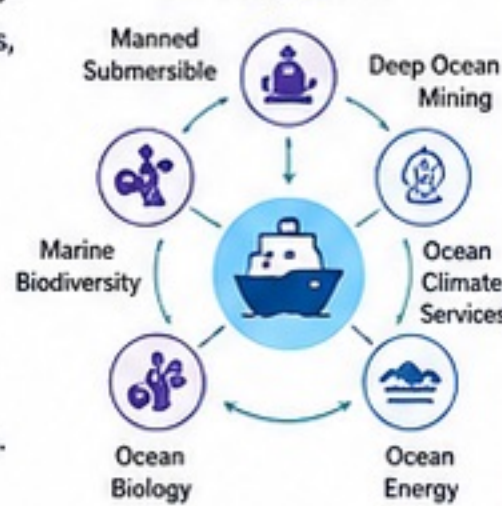
Value Addition: Strengthens Atmanirbhar Bharat & sustainable rural livelihoods.

Keywords: Sustainable Agriculture, Soil Health, Agroecology

4 Deep Ocean Mission

- Flagship mission for Blue Economy.
- Explores deep ocean for resources, energy & biodiversity.
- Six components: submersible, mining, climate services, energy, biodiversity, biology.
- Supports ocean science & marine conservation.
- Helps in discovery of critical minerals.
- Strengthens maritime capabilities.
- Aligned with SDG 14.

Six Components



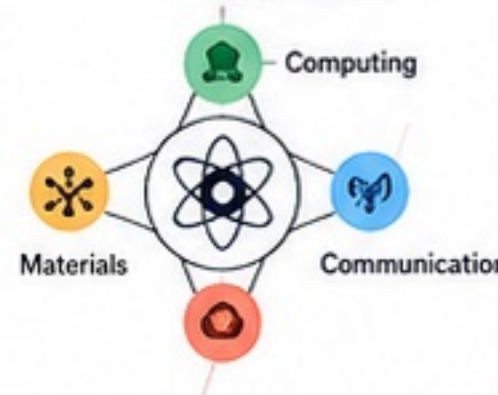
Value Addition: Key driver of India's Blue Economy & ocean-based strategic advantage.

Keywords: Blue Economy, Marine Resources, UNCLOS

5 National Quantum Mission

- Approved in 2023 to build quantum technology ecosystem.
- Four thrust areas: computing, communication, sensors & materials.
- Applications in defence, cybersecurity, healthcare, finance & weather.
- Focus on indigenous R&D & start-up ecosystem.
- High-impact emerging technology.
- Strengthens India's global tech leadership.
- Long-term strategic advantage.

Quantum Technology Applications



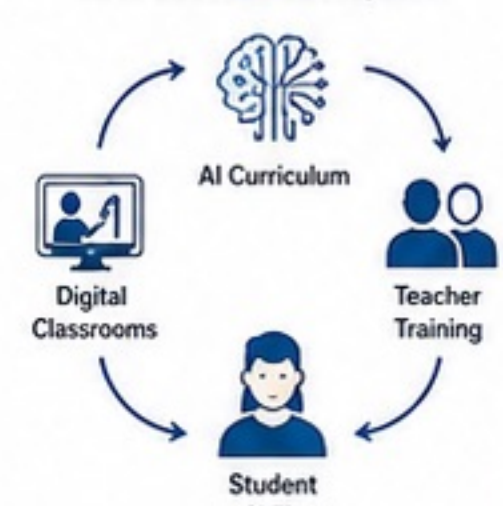
Value Addition: Critical for future industries & national security.

Keywords: Quantum Computing, Innovation, Emerging Tech

6 AI & Digital Education in Schools

- AI education integrated in school curriculum.
- Focus on AI literacy, coding & future-ready skills.
- Centres of Excellence for AI & digital learning.
- Digital classrooms & teacher training expanded.
- Initiatives: PM SHRI, DIKSHA, SWAYAM, NDEAR.
- Bridges digital divide in education.
- Prepares youth for future jobs.

AI in Education Ecosystem



Value Addition: Builds human capital for Digital India & knowledge economy.

Keywords: AI Literacy, Digital India, Education Reform

7 Cross-Border Paperless Trade Framework

- Inventory-based Cross-border E-commerce Export Framework under FTP 2023.
- Digital documentation & warehouse integration.
- Faster customs clearance & lower transaction cost.
- Promotes MSME exports.
- Improves Ease of Doing Business.
- Enhances global competitiveness.
- Supports "Make in India".

Paperless Trade Flow



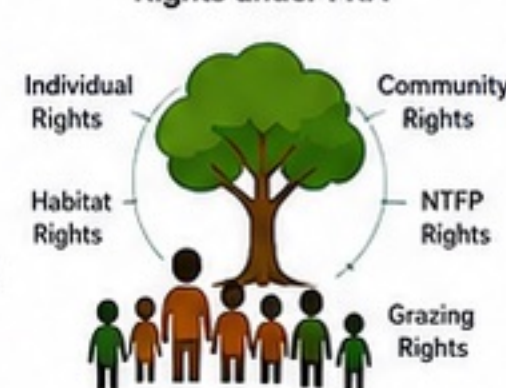
Value Addition: Boosts exports & supports Atmanirbhar Bharat.

Keywords: FTP 2023, E-commerce, Trade Facilitation

8 Forest Rights Act (FRA), 2006

- Recognises rights of forest dwelling communities.
- Grants individual & community forest rights.
- Covers habitat, grazing, NTFP & resource management.
- Gram Sabha plays central role.
- Strengthens tribal empowerment & conservation.
- Balances development & environment.
- Ensures social justice.

Rights under FRA



Value Addition: Promotes inclusive growth & biodiversity conservation.

Keywords: Tribal Rights, Governance, Social Justice

9 Roadmap for India's EV Ecosystem

- Comprehensive roadmap for EV manufacturing & adoption.
- Initiatives: PM E-DRIVE, FAME, PLI (ACC Batteries).
- Focus on charging infrastructure & battery ecosystem.
- Reduces oil imports & emissions.
- Boosts green manufacturing & employment.
- Supports Net Zero 2070 goal.
- Advances sustainable mobility.

EV Ecosystem



Value Addition: Drives green growth & energy security.

Keywords: EV, Clean Mobility, Climate Action

Other Important One-Liners



Fiscal Health Index (FHI) 2025 released – assesses states on quality of fiscal management.



New study shows rainfall impacts elephant movement in southern Western Ghats.



SC emphasizes fair & lawful citizenship rulings; stays ban on cow slaughter in TN.



India-Japan review defence ties; preparation for 2+2 dialogue.



Efficient method developed for filtering nuclear wastewater.

1 The Union Cabinet has approved the PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana to boost agricultural productivity. What is its duration?

- A) 3 years
- B) 4 years
- C) 5 years
- D) 6 years



2 India has successfully test-fired the indigenously developed short-range ballistic missile 'Pralay'. What is its approximate range?

- A) 150 km
- B) 250 km
- C) 350 km
- D) 500 km



3 Which institution has released India's first district-level climate risk assessment report under the CRVA initiative?

- A) NITI Aayog
- B) Indian Council of Agricultural Research
- C) Indian Institute of Tropical Meteorology
- D) Council on Energy, Environment & Water



4 India and which country have recently signed a MoU on Green Shipping Corridors to promote sustainable maritime transport?

- A) Japan
- B) United Kingdom
- C) France
- D) Norway



5 The government has launched 'RuPay Credit on UPI' to enhance digital credit access. What is the key feature of this facility?

- A) Credit card on UPI
- B) Instant pre-approved credit line on UPI
- C) Loan transfer on UPI
- D) Cash withdrawal on UPI



6 Recently, the government has launched the 'National Cold-chain and Value Addition Infrastructure' initiative under which ministry?

- A) Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
- B) Ministry of Food Processing Industries
- C) Ministry of Commerce & Industry
- D) Ministry of Rural Development



7 India hosted the 3rd Voice of Global South Summit 2026 in which city?

- A) Bengaluru
- B) Hyderabad
- C) New Delhi
- D) Mumbai



8 ISRO has recently signed an agreement with which country's space agency for joint earth observation satellite mission?

- A) United States (NASA)
- B) Russia (Roscosmos)
- C) France (CNES)
- D) Australia (ASI)



9 Which state government has launched 'Mukhyamantri Van Sampada Yojana' to promote forest produce-based livelihoods?

- A) Madhya Pradesh
- B) Chhattisgarh
- C) Odisha
- D) Jharkhand



1

NEWS AT A GLANCE

Essential stockpiling for a mineral-driven future

OPINION

Meheli Roy Choudhury

Effective stockpiling of critical minerals is crucial to ensure supply security, price stability, and economic resilience. The article highlights the need for coordinated, technology-driven, and market-sensitive strategies to build and manage reserves of minerals like cobalt, lithium, rare earth elements, copper, natural gas and coal.

India must adopt a multi-layered approach involving trusted partnerships, strategic reserves, price bands, and dual protection against both market shocks and supply disruptions.



Precious goods: A sample of rare earth materials at Australian mining company Viridis Mining. REUTERS

2

WHY STOCKPILING MATTERS?

- **Supply Security:** Ensures availability during geopolitical tensions, natural disasters or trade restrictions.
- **Price Stability:** Reduces extreme price volatility caused by market speculation or sudden demand.
- **Strategic Autonomy:** Supports defence, energy transition and advanced technology needs.
- **Industrial Resilience:** Prevents production disruptions and secures critical supply chains.
- **Economic Safety Net:** Acts as a buffer during market shocks and external supply disruptions.



3

WHAT TO STOCKPILE?

Focus on critical & strategic minerals



Lithium
Batteries, EVs



Cobalt
Batteries, Alloys



Rare Earth Elements
Magnets, Electronics



Copper
Electrical, Industrial Infrastructure



Natural Gas
Energy Security & Transition



Coal
Power Generation (Base Load)

Diverse portfolio = Lower risk + Higher resilience

4

PRINCIPLES OF EFFECTIVE STOCKPILING

- Multilateral & trusted partnerships for pooling storage costs.
- Dynamic price bands as safety hatch for market stability.
- Layered reserves: Strategic, operational & commercial levels.
- Rotation & utilisation to prevent degradation and obsolescence.
- Infrastructure readiness: Storage, refining, logistics and technology.
- Data-driven planning using demand forecasts and scenario analysis.



Right stock • Right time • Right cost • Right place

5

RISKS & CHALLENGES

- High cost of storage & maintenance.
- Risk of resource degradation over time.
- Rapid technology change reduces relevance of some minerals.
- Geopolitical concentration of mineral supply.
- Market distortions due to poorly designed reserves.
- Coordination challenges among ministries, agencies and PSUs.



To succeed: Balance security needs with market dynamics and fiscal prudence.

6

INDIA'S WAY FORWARD

- Implement National Critical Mineral Mission with speed.
- Create strategic reserves for key minerals.
- Diversify imports & secure long-term contracts.
- Invest in domestic exploration, mining and processing.
- Boost recycling & circular economy.
- Develop advanced storage and refining infrastructure.



Atmanirbhar Bharat in minerals = Energy security + Economic strength + Strategic autonomy

7

MCQ PRACTICE

Q. Which of the following minerals are specifically highlighted in the article as important for batteries and electric vehicles?

- Iron ore and Bauxite
- Lithium and Cobalt
- Gold and Silver
- Uranium and Thorium



Answer: (b) Lithium and Cobalt

The article mentions lithium and cobalt as critical minerals used in batteries and electric vehicles.

8

QUICK REVISION POINTS

- ✓ Stockpiling ensures supply security and price stability in uncertain times.
- 🔗 Critical minerals drive energy transition, electronics, defence and clean technologies.
- 👥 India's strategy requires: partnerships, layered reserves, rotation, infrastructure and data.
- 📈 Risks include high cost, degradation, tech change, geopolitical concentration and market distortion.
- 🎯 Goal: Build resilient, cost-effective and future-ready stockpiling ecosystem.

Secure today's resources for tomorrow's growth.

9

MAINS DISCUSSION QUESTION



Critical minerals are the backbone of India's energy transition, technology ambitions and strategic autonomy. Discuss the significance of mineral stockpiling for India and examine the challenges in building an effective and sustainable stockpiling strategy.

(15 Marks, 250 Words)

1

NEWS AT A GLANCE

What can be done to curb 'paper leaks' and ensure institutional accountability?

Despite the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, the need to fix accountability for detecting breaches, preventing them and preserving the integrity of public examinations remains

Rajeev Kumar

N EET row has reignited the debate on paper leaks, exposing flaws in the examination ecosystem. The article highlights the need for accountability, technology-driven solutions, transparency and strong institutional mechanisms.

The CBI, NTA and other agencies are investigating, while stricter laws and operational reforms are essential to restore public confidence.



Students entering an examination centre in Udupi during the NEET exam.
FILE PHOTO

2

WHAT IS A 'PAPER LEAK'?

- Unauthorized disclosure of question paper before or during the examination.
- May occur at printing, packaging, transportation, storage or digital dissemination stages.
- Enables unfair advantage, violates merit and equality.
- Includes compromised systems, insider leaks, or external criminal syndicates.
- Harms credibility, creates anxiety and delays examinations.
- Erodes public trust in institutions and governance.



Paper leaks destroy meritocracy and weaken institutional credibility.

3

WHY DO PAPER LEAKS HAPPEN?



Insider involvement and human collusion.



Weak security at printing, storage, transportation and examination centres.



Use of technology and digital platforms for malpractice.



Lack of coordination and accountability among agencies.



High stakes, coaching mafia and commercial exploitation.

Impact



Compromises merit and fairness



Denies opportunities to genuine candidates



Wastage of time, money and resources



Loss of confidence in governance

Leakage = Failure of systems, not just individuals.

4

LEGAL & INSTITUTIONAL FRAMEWORK

- Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024: Central law to prevent and penalise leaks.
- IPC & IT Act: Provisions on criminal breach, cheating and cyber offences.
- National Testing Agency (NTA): Conducts major exams at national level.
- CBI: Investigates major leaks on government request.
- States: Local police, special task forces and exam regulatory bodies.



Strong laws exist; implementation and accountability are the real challenges.

5

WHAT CAN BE DONE?



Secure the entire examination lifecycle.



End-to-end encryption of question papers.



Randomisation of question papers & shifts.



Digital distribution with access control.



GPS-tracked transportation & storage.



AI-based monitoring & anomaly detection.



Strict vetting of personnel; background checks.



Whistleblower protection & incentives.



Transparent communication & prompt action.

Technology + Process + People + Accountability
= Leak-proof examination system.

6

ROLE OF STAKEHOLDERS

- Government: Policy, resources, technology, strict enforcement.
- Exam Conducting Bodies: Standard operating procedures, audits, transparency.
- Law Enforcement: Swift investigation and deterrent punishment.
- Judiciary: Fast-track courts for examination offences.
- Society & Media: Responsible reporting and zero tolerance to malpractice.



Accountability must be collective, continuous and non-negotiable.

7

MCQ PRACTICE

Q. Consider the following statements about the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024:



1. It is a Central Act to prevent and penalise unfair means in public examinations.
2. It applies to all examinations conducted by private institutions.
3. It provides for creation of a National Council to maintain exam integrity.

Which of the statements given above is/are correct?

- a) 1 and 2 only b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only d) 1, 2 and 3

Answer: (b) 1 and 3 only

Explanation: Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect as it applies to public examinations. Statement 3 is correct as it provides for a National Council.

8

QUICK REVISION POINTS



Paper leaks violate Article 14 (equality) and Article 16 (equality of opportunity in public employment).



Integrity of exams is essential for merit, transparency and social justice.



Comprehensive approach: Law + Technology + Process Reform + Accountability.



Need for coordination among NTA, CBI, States, courts and cybersecurity agencies.



Invest in secure infrastructure, capacity building and digital forensics.

Credible examinations = Credible institutions =
Confident nation.

9

MAINS DISCUSSION QUESTION



Paper leaks reflect a serious failure of governance and institutional accountability. Discuss the structural reforms, technological interventions and accountability mechanisms needed to ensure the integrity of public examinations in India.

(15 Marks, 250 Words)

Newspaper Notes

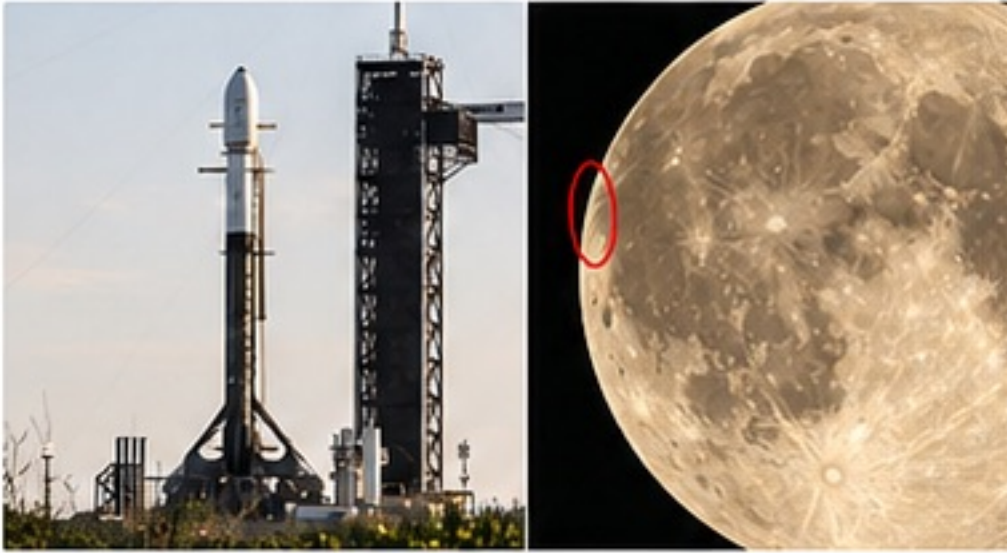
(15 Marks, 250 Words)

1

NEWS AT A GLANCE

SpaceX rocket stage hurtles toward moon, astronomers hot on its trail

This Falcon 9 rocket had launched two satellites towards the moon in January 2025; now expected to hit the moon at 12:05 p.m. IST on Aug 5



2

WHAT HAPPENED?

- Falcon 9 rocket launched in Jan 2025 with two lunar satellites.
- SpaceX later abandoned the spent upper stage.
- Lacked enough fuel to return to Earth or enter deep space orbit.
- Now predicted to crash on the Moon at 12:05 p.m. IST on 5 Aug 2026.
- Independent calculations point to impact on the Einstein Crater.



3

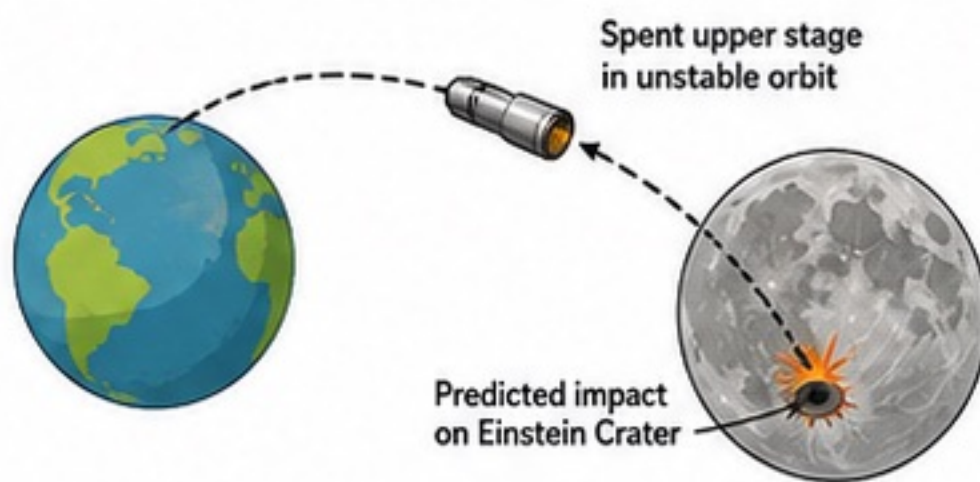
WHY IS IT IMPORTANT?

- First random rocket impact on the Moon from human activity.
- Opportunity to study fresh impact crater formation.
- Helps understand ejecta, debris, and vapor clouds.
- Artificial impacts are rare and valuable for science.
- Improves knowledge of lunar surface evolution and seismic activity.
- Supports planning for future lunar missions and safety.



4

SCIENCE BEHIND THE IMPACT



Impact Speed: ~8,700 km/h

- Impact speed estimated ~8,700 km/h.
- Creates a new crater, ejecta plume & seismic waves.
- Vaporised material may form a temporary cloud.
- Data useful for impact modelling & lunar geology.

5

KEY CONCERNS

- Space debris is a growing challenge.
- Uncontrolled objects can endanger satellites & missions.
- Need for responsible disposal of rocket stages.
- International guidelines for space traffic management are limited.
- Increasing private launches raise long-term sustainability concerns.



Space sustainability is essential for safe & inclusive exploration.

6

GLOBAL & POLICY CONTEXT

- Outer Space Treaty (1967): Peaceful use, liability for damage.
- No specific rules for deliberate or accidental impacts.
- Need for global norms on debris mitigation.
- UN COPUOS & IADC working on long-term sustainability.
- Important for future lunar bases, mining & missions.



Sustainable space activities require global cooperation, transparency and accountability.

7

QUICK REVISION (STATIC LINKAGES)

- ISRO: Chandrayaan-1, 2, 3 missions to Moon.
- Outer Space Treaty, 1967
 - Liability Convention, 1972
 - Registration Convention, 1975
- Launch vehicles & orbital mechanics.
- Seismology & planetary geology.
- Space debris: Kessler Syndrome.



8

MCQ PRACTICE

Q. The Falcon 9 rocket stage discussed in the news is expected to crash on the Moon near which crater?

- Tycho Crater
- Einstein Crater
- Copernicus Crater
- Kepler Crater



Answer: (b) Einstein Crater

The independent calculations indicate impact near the Einstein Crater on 5 Aug 2026.

9

MAINS DISCUSSION QUESTION



With the increasing frequency of space missions by both public and private agencies, discuss the challenges posed by space debris and suggest measures to ensure long-term sustainability of outer space activities.

(15 Marks, 250 Words)

1 SC ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर रोक के लिए केंद्र को SOPs बनाने का निर्देश दिया



- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से डिजिटल अरेस्ट घोटालों रोकने हेतु SOPs बनाने को कहा।
- मानक परिचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) तैयार करने का निर्देश।
- वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और धमकी पर रोक पर जोर।
- पुलिस, न्यायालय, CBI, ED आदि के बीच समन्वय आवश्यक।
- VoIP कॉल्स, AI क्लोनिंग और पहचान स्फूर्ति के दुरुपयोग को रेखांकित।
- तकनीकी विनियमन और जागरूकता की तत्काल आवश्यकता।
- याचिकाओं तबिल—अदालत ने जल्द प्रतिक्रिया मांगी।

अनुच्छेद 21 • साइबर अपराध • IT अधिनियम SOPs • डिजिटल धोखाधड़ी • जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार

2 राइट टू बी फॉरगॉटन: कर्नाटक HC ने बरी महिला का नाम ऑनलाइन स्रोतों में छिपाने की अनुमति दी



- Search
- कर्नाटक हाई कोर्ट ने 'भूलने के अधिकार' को मौलिक अधिकार माना।
 - न्यायालय ने कहा—बरी महिला का नाम ऑनलाइन स्रोतों में मास्क किया जाए।
 - निजता, गरिमा और पुनर्वास के अधिकार को संरक्षण।
 - सर्व इंजन और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म को निर्देश लागू करना होगा।
 - अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार) के साथ संतुलन।
 - पुडुच्चामी जजमेंट (2017) का अनुसरण।
 - ऑनलाइन प्रतिष्ठा के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय।

अनुच्छेद 21 • राइट टू बी फॉरगॉटन • निजता का अधिकार पुडुच्चामी केस • गरिमा • पुनर्वास

3 खनिज-चालित भविष्य के लिए आवश्यक भंडारण (स्टॉकपाइलिंग)



- ऊर्जा संक्रमण और हरित प्रौद्योगिकी हेतु महत्वपूर्ण खनिजों की मांग तेज़।
- आपूर्ति शृंखला की कमजोरियों को कम करने के लिए रणनीतिक भंडारण अनिवार्य।
- EVs, बैटरी, सेमीकंडक्टर, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा: संसाधनों पर देशों की होड़।
- आयात निर्भरता से जोखिम—कीमत, आपूर्ति बाधित और भू-राजनीतिक दबाव।
- भारत को विविध स्रोतों, द्विपक्षीय साझेदारी और परेल् अन्वेषण की जरूरत।
- आत्मनिर्भर भारत, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम।

महत्वपूर्ण खनिज • ऊर्जा सुरक्षा • आपूर्ति शृंखला रणनीतिक भंडारण • EVs • आत्मनिर्भर भारत

त्वरित समाचार (Quick News)

- 1 खनिज-चालित भविष्य के लिए आवश्यक भंडारण भारत जरूरी खनिजों के भंडार बढ़ाएगा ताकि आपूर्ति निर्भरता कम हो और उद्योग को मजबूती मिले।
- 2 10-किमी खनन बफर सभी आर्द्रभूमि रिजर्व पर लागू: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा—सभी आर्द्रभूमि रिजर्व के चारों ओर 10-किमी बफर क्षेत्रों में खनन नहीं होगा।
- 3 दुनिया के सबसे छोटे द्वीपीय राष्ट्र ने बदला अपना नाम औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति के लिए देश ने अपने आधिकारिक नाम में बदलाव किया।
- 4 'सिक्स-सैन-वन वैक्सीन से टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा मिल सकता है' विशेषज्ञों का कहना—नई वैक्सीन से कई बीमारियों के खिलाफ बेहतर संरक्षण मिलेगा।
- 5 WHO अनुसंधान एजेंसी ने 3 सोकप्रिय दवाओं को कांसिनोजेनिक घोषित किया IARC ने तीन आम दवाओं को मानव के लिए संभावित कांसिनोजेन बताया।
- 6 सरकार ने 'भारत में व्यापार करना आसान बनाने' के लिए श्रित पेश किया श्रित का उद्देश्य प्रक्रिया सरल करना, अनुपालन बोझ कम करना और व्यापार सुगमता बढ़ाना है।
- 7 टेस्ला की चीन में मजबूत उपस्थिति, संभावित SpaceX मर्जर का रोडमैप जटिल बनाएगी निवामकीय और भू-राजनीतिक घिंताएँ Tesla और SpaceX के विलय को प्रभावित कर सकती हैं।
- 8 चीन के बढ़ते खतरे के बीच जापान ने कॉन्वैट ड्रोन पर दांव लगाया क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जापान ड्रोन तकनीक और रक्षा क्षमता बढ़ा रहा है।
- 9 ऑनलाइन अफवाहों से मोरक्को से स्पूटा तक प्रवासियों की भारी भीड़ उमड़ी अफवाहों के कारण स्पूटा सीमा पार करने की जल्दबाजी से स्थिति अस्थिर हुई।

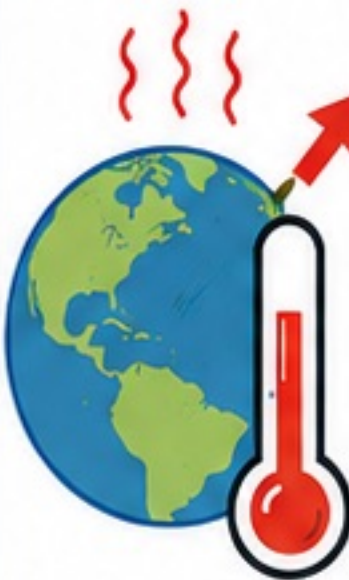
4 स्पेसएक्स रॉकेट स्टेज चंद्रमा की ओर, वैज्ञानिक उसकी तलाश में



- उपयोग किया गया SpaceX रॉकेट स्टेज चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है।
- वैज्ञानिक इसकी ट्रेकिंग कर रहे हैं।
- यह धरण पृथ्वी की कक्षा से निकलकर गहरे अंतरिक्ष में गया।
- गैर-नियंत्रित ऑर्बिटल डेट्रिस से टकराव और प्रदूषण का खतरा।
- अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन वैश्विक चुनौती।
- अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन (STM) की आवश्यकता।
- टिकाऊ अंतरिक्ष उपयोग हेतु वैश्विक मानकों की मांग।

अंतरिक्ष मलबा • स्पेस सुरक्षा • चंद्रमा मिशन Falcon 9 • अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन • STM

5 वैश्विक तापवृद्धि: गति तेज़



- वैश्विक तापवृद्धि अपेक्षा से तेज गति से बढ़ रही है।
- मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मुख्य कारण।
- चरम मौसम घटनाएँ—बाढ़, सूखा, गर्मी की लहरें बढ़ी।
- पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा।
- COP28 के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु तात्कालिक कार्य आवश्यक।
- अनुकूलन और शमन कदमों को तेज करना होगा।
- जलवायु न्याय और समानता पर जोर।

जलवायु परिवर्तन • IPCC • COP28 • नेट जीरो अनुकूलन • शमन • पेरिस समझौता

6 टॉप स्पॉट (संपादकीय)



- वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती स्थिति पर संपादकीय टिप्पणी।
- अर्थव्यवस्था, तकनीक, कूटनीति में उपलब्धियों को रेखांकित।
- संरचनात्मक सुधार और नवाचार की सराहना।
- शिक्षा, कौशल व अनुसंधान में निवेश पर बल।
- सुशासन और संस्थागत सुदृढ़ता को मजबूती।
- समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की आवश्यकता।
- श्रिष्ठ शक्ति के रूप में भारत की भूमिका पर जोर।

वैश्विक रैंकिंग • सुशासन • सुधार • समावेशी विकास मानव पूंजी • नवाचार • संस्थागत मजबूती

7 NATO एक नए रणनीतिक युग में परिवर्तन के दौर में (संपादकीय)



- NATO नई वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के अनुकूल हो रहा है।
- सामूहिक रक्षा, निवारक क्षमता और लचीलापन पर फोकस।
- चीन और हाइब्रिड खतरों की बढ़ती चुनौती का सामना।
- तकनीक, साइबर और अंतरिक्ष पर निवेश बढ़ाना।
- इंडो-पैसिफिक में साझेदारी मजबूत करना।
- सामूहिक सुरक्षा और नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन।
- परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में रणनीतिक विस्तार।

NATO • सामूहिक रक्षा • इंडो-पैसिफिक नियम-आधारित व्यवस्था • लचीलापन

8 बेरोजगार और आक्रोशित (टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट)



- बढ़ती बेरोजगारी से युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है।
- शिक्षा और कौशल में असमानता बढ़ी समस्या।
- सामाजिक स्थिरता और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव।
- रोजगार सृजन की गति पर्याप्त नहीं।
- MSMEs और स्टार्टअप्स को समर्थन की आवश्यकता।
- समावेशी विकास और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर।
- जनांकिकीय लाभांश को संभालना बढ़ी चुनौती।

बेरोजगारी • युवाओं की समस्या • कौशल MSMEs • समावेशी विकास • जनांकिकीय लाभांश

9 पेपर लीक कैसे रोकें और संस्थागत जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करें? (कैच)



- पेपर लीक से योग्यता और विश्वास को नुकसान।
- कड़ा कानूनी ढांचा व दंड आवश्यक।
- सुरक्षित परीक्षा प्रणाली और तकनीकी निगरानी जरूरी।
- भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ो।
- अधिकारियों की जवाबदेहीतय हो।
- समयबद्ध जांच और कठोर दंड।
- डिजिटल ट्रेकिंग और एक्लिप्शन का प्रयोग।
- नैतिक प्रशासन और परीक्षा की साख की रक्षा।

परीक्षा अखंडता • लीक रोकथाम • जवाबदेही तकनीकी सुरक्षा • पारदर्शिता • सुशासन

प्रिलिम फैक्ट्स (Prelim Facts)

- 1 अनुच्छेद 21 – निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है।
- 2 पुडुच्चामी बनाम UOI (2017) – निजता को मौलिक अधिकार माना गया।
- 3 महत्वपूर्ण खनिज – लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रैयर अर्थ, कॉपर आदि।
- 4 पेरिस समझौता – 2015; लक्ष्य: वैश्विक तापवृद्धि 2°C से नीचे रखना।
- 5 नेट जीरो लक्ष्य – भारत ने 2070 तक का लक्ष्य घोषित किया।
- 6 NATO – गठन 1949; सामूहिक रक्षा गठबंधन (अनुच्छेद 5 सिद्धांत)।
- 7 IARC (WHO) – अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर।
- 8 IT अधिनियम, 2000 – साइबर अपराध और डिजिटल प्रमाणों से संबंधित।
- 9 अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) – वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उत्कृष्टता की भावना विकसित करना।

अपना अंग्रेजी जानें (Know Your English)

- 1 Turbulence (नाउन) – अशांति Example: The flight hit turbulence.
- 2 Acquitted (वर्ब) – दोषमुक्त करना Example: The court acquitted him of all charges.
- 3 Derogatory (एड्जेक्टिव) – अपमानजनक Example: He made derogatory remarks.
- 4 Whisked (वर्ब) – जल्दी ले जाया जाना Example: He was whisked away by the police.
- 5 Anticipatory (एड्जेक्टिव) – पूर्वानुमानित/पूर्वानुमानित Example: He filed an anticipatory bail petition.
- 6 Posse (नाउन) – सुरक्षा दल Example: He was accompanied by a posse.
- 7 VoIP (नाउन) – इंटरनेट कॉल प्रोटोकॉल Example: VoIP calls are used worldwide.
- 8 Reputation (नाउन) – मर्यादा/सम्मान Example: He built a good reputation.
- 9 Precedent (नाउन) – मिसाल/पूर्व निर्णय Example: This case will set an important precedent.

1 SC directs Centre to frame SOPs to curb 'digital arrest' scams



- Supreme Court seeks Centre's response on digital arrest scams.
- Centre directed to frame Standard Operating Procedures (SOPs).
- Aim: Prevent fraud, protect citizens' liberty & financial security.
- Involves impersonation by fake police, courts, CBI, ED, etc.
- Misuse of VoIP calls, AI cloning & identity spoofing.
- Rising cases highlight urgent need for tech-regulation & awareness.
- Public interest litigation pending before the Court.

Article 21 • Cyber Crime • IT Act • SOPs
Digital Fraud • Right to Life & Liberty

2 Right to be forgotten: Karnataka HC lets name of acquitted woman be masked in online sources

search



NAME
MASKED

- Karnataka High Court upheld right to be forgotten.
- Name of woman acquitted in case to be masked online.
- Protects privacy, dignity & rehabilitation.
- Applies to search engines & public digital platforms.
- Balances Article 21 (privacy) with freedom of speech.
- Follows Puttaswamy judgment (2017) on privacy.
- Sets precedent for digital reputation protection.

Article 21 • Privacy • Right to be Forgotten
Digital Rights • Puttaswamy Case

3 Essential stockpiling for a mineral-driven future



- Essential minerals critical for green transition & technology.
- Stockpiling reduces supply chain vulnerabilities.
- Needed for EVs, batteries, semiconductors, renewables & defence.
- Global competition for resources intensifying.
- India's import dependence poses risks.
- Calls for strategic reserves & diversified sourcing.
- Key to Atmanirbhar Bharat & energy security.

Critical Minerals • Energy Security • EVs
Strategic Reserves • Self-Reliance

4 SpaceX rocket stage hurtles toward moon, astronomers hot on its trail



- Spent SpaceX rocket stage heading toward the Moon.
- Astronomers tracking its trajectory.
- Part of Falcon 9 mission (Earth orbit launch).
- Space debris raising concerns.
- Risk of impact & lunar contamination.
- Highlights need for space traffic management.
- Calls for global norms on space sustainability.

Outer Space • Space Debris • Space Security
Falcon 9 • Space Traffic Management

5 Global warming: picking speed



- Global warming accelerating faster than expected.
- Human-induced emissions main driver.
- Extreme weather events increasing worldwide.
- Threat to ecosystems, food security & health.
- COP28 commitments need urgent action.
- Adaptation & mitigation must scale up.
- Equity & climate justice essential.

Climate Change • IPCC • COP28 • Net Zero
Mitigation • Adaptation • Paris Agreement

6 Top spot (Editorial)



- Editorial on India's global standing.
- Highlights achievements in key sectors.
- Calls for sustained reforms & innovation.
- Emphasis on education, skills & research.
- Strengthening governance & institutions.
- Need for inclusive growth & social justice.
- Positioning India as a leading power.

Global Ranking • Governance • Reform
Inclusive Growth • Human Capital

7 NATO enters a new strategic era of transformation (Editorial)



- NATO adapts to new global security challenges.
- Focus on deterrence, defence & resilience.
- Countering Russia, China & hybrid threats.
- Investment in technology, cyber & defence.
- Strengthening partnerships in Indo-Pacific.
- Collective security & rules-based order stressed.
- Transformation for a volatile world.

NATO • Collective Security • Indo-Pacific
Deterrence • Rules-Based Order

8 Out of work and outraged (Text & Context)



- Rising unemployment fuels public anger.
- Youth unemployment a serious concern.
- Impact on social stability & mental health.
- Need for job creation in manufacturing & services.
- Skilling, MSMEs & start-ups key to solution.
- Inclusive growth & policy support essential.
- Demographic dividend at risk.

Unemployment • Demography • Skilling
MSMEs • Inclusive Growth

9 What can be done to curb 'paper leaks' and ensure institutional accountability? (Cache)



- Paper leaks undermine merit & trust.
- Need strict legal framework & deterrence.
- Tech-enabled secure exam systems.
- Transparency in recruitment process.
- Accountability of officials mandatory.
- Time-bound probe & punishment.
- Holistic reform for integrity in exams.

Exam Integrity • Leak Prevention • Accountability
Technology • Transparency • Governance

QUICK NEWS

- Essential stockpiling for a mineral-driven future**
India must build reserves of critical minerals to reduce import dependence and supply chain risks.
- 10-km mining buffer applies to all wetland reserves: top court**
Supreme Court extends 10-km no-mining buffer to all wetland reserves across India.
- World's smallest island nation revises its name to shed colonial vestiges**
King Charles honours request of island nation to adopt indigenous name.
- 'Six-in-one vaccine may boost immunisation programme'**
Expert panel recommends inclusion of Hexavalent vaccine to strengthen coverage.
- 3 widely used medicines classified as carcinogenic by WHO research agency**
IARC classifies three common medicines as possibly carcinogenic to humans.
- Govt. introduces Bill to 'make it easier to do business in India'**
Bill aims to simplify rules, reduce compliance burden and promote ease of doing business.
- Tesla's China footprint complicates roadmap to possible SpaceX merger**
Regulatory and geopolitical concerns over Tesla's deep China ties may affect SpaceX merger plans.
- Japan bets on combat drones amid growing Chinese threat in the region**
Japan accelerates development of combat drones to counter China's military build-up.
- Online rumours sparked frantic rush of migrants from Morocco to Ceuta**
False online rumours led to stampede-like rush at Ceuta border crossing.

PRELIM FACTS

- Right to Privacy is a Fundamental Right under Article 21.
- Puttaswamy Judgment (2017) recognized privacy as a fundamental right.
- Critical minerals include Lithium, Cobalt, Nickel, Rare Earths, Copper.
- Paris Agreement adopted in 2015; India committed to Net Zero by 2070.
- NATO was formed in 1949 as a collective defence alliance.
- IARC (International Agency for Research on Cancer) is a WHO body.
- MSMEs contribute ~30% to India's GDP and ~40% to exports.
- Information Technology Act, 2000 governs cyber crimes in India.
- Article 51A (Fundamental Duties) includes value of scientific temper & excellence.

KNOW YOUR ENGLISH

- Turbulence** (noun) – a state of great disturbance
- Accused** (adjective) – charged with a crime
- Derogatory** (adjective) – showing strong disapproval
- Whisked** (verb) – taken somewhere quickly
- Anticipatory** (adjective) – done in advance
- Posse** (noun) – a group of people assembled for a purpose
- VoIP** (noun) – Voice over Internet Protocol
- Reputation** (noun) – the opinion people have about you
- Precedent** (noun) – an example decided in law or action

1. The news of his promotion made him feel _____.



- | | |
|------------|----------------|
| a) upset | b) thrilled |
| c) nervous | d) indifferent |

2. The old watch still works _____ after so many years.



- | | |
|-----------|-----------|
| a) well | b) badly |
| c) hardly | d) rarely |

3. He remained calm and _____ in a difficult situation.



- | | |
|-------------|--------------|
| a) composed | b) confused |
| c) excited | d) irritated |

4. The teacher gave a _____ explanation of the topic.



- | | |
|--------------|----------|
| a) vague | b) clear |
| c) confusing | d) brief |

5. The child looked _____ when he lost his toy.



- | | |
|-----------------|--------------|
| a) delighted | b) cheerful |
| c) disappointed | d) surprised |

6. She is a _____ worker who always meets her deadlines.



- | | |
|-------------|----------------|
| a) careless | b) diligent |
| c) lazy | d) indifferent |

7. The heavy rain caused _____ in the city.



- | | |
|------------|-----------|
| a) traffic | b) hunger |
| c) peace | d) joy |

8. Please keep your voice _____ during the library hours.



- | | |
|----------|-----------|
| a) high | b) silent |
| c) harsh | d) angry |

9. The team celebrated their victory with great _____.



- | | |
|-----------|---------------|
| a) sorrow | b) excitement |
| c) fear | d) regret |

Q1: "National integration is strengthened not by suppressing diversity but by accommodating it within constitutional limits." Discuss.



1 UNDERSTANDING THE STATEMENT

- India is a land of unity in diversity.
- Suppression breeds alienation and conflict.
- Accommodation within constitutional limits fosters respect and harmony.



2 CONSTITUTIONAL FOUNDATION

- Preamble: Unity and integrity of the Nation.
- Articles 14, 15, 16: Equality and non-discrimination.
- Articles 29, 30: Protection of culture, language and educational rights.
- Federal structure (Seventh Schedule) respects regional aspirations.



3 ACCOMMODATION OF DIVERSITY IN PRACTICE

- Linguistic reorganisation of States (States Reorganisation Act, 1956).
- Recognition of multiple languages in the Eighth Schedule.
- Personal laws, cultural rights and minority institutions.
- Panchayati Raj & local self-government for local needs.



4 ROLE OF INSTITUTIONS & POLICIES

- Election Commission ensures equal participation.
- Inter-State Council, NITI Aayog promote cooperative federalism.
- Schemes for backward regions (NER, LWE areas, tribal belts).
- Affirmative action for SCs, STs, OBCs and minorities.



5 BENEFITS OF ACCOMMODATION

- Strengthens national unity and social cohesion.
- Reduces alienation and separatist tendencies.
- Encourages cultural exchange and mutual respect.
- Inclusive growth and balanced development.



6 RISKS OF SUPPRESSING DIVERSITY

- Leads to resentment, protests and separatism.
- Erosion of trust; loss of faith in the Constitution.
- Creates 'us vs them' mentality.
- Threatens internal security and development.



7 CHALLENGES

- Rising identity politics and vote bank approach.
- Regional disparities and perceived injustice.
- Majoritarian tendencies and intolerance.
- Weak implementation of development schemes.



8 WAY FORWARD

- Uphold constitutional morality and rule of law.
- Promote inclusive development and equal opportunities.
- Strengthen interfaith dialogue and cultural exchange.
- Civic education and awareness on constitutional values.



Q2: "How do misinformation and social media contribute to communal polarization?"



1 SPREAD OF MISINFORMATION

- False or misleading content shared as facts.
- Context is twisted; old videos shared as new.
- Rumours spread faster than verified information.



2 ALGORITHMIC AMPLIFICATION

- Algorithms favour sensational and emotional content.
- Creates echo chambers and filter bubbles.
- Reinforces biases and extreme views.



3 EMOTIONAL TRIGGERS

- Content targeted at religious sentiments and identity.
- Uses fear, anger, pride to manipulate emotions.
- Emotional content leads to impulsive sharing.



4 VIRALITY & SPEED

- Information spreads in seconds to thousands.
- Forwarding before verification becomes common.
- Mob reactions are often triggered online.



5 TARGETED PROPAGANDA

- Coordinated campaigns by organized groups.
- Use of bots, fake accounts and paid trends.
- Aimed at polarizing communities and influencing opinions.



6 IMPACT ON COMMUNAL HARMONY

- Creates distrust and hatred between communities.
- Leads to tensions, violence and loss of lives.
- Damage to social fabric and national integration.



7 LEGAL & REGULATORY RESPONSE

- IT Act, 2000 & IT (Intermediary Guidelines) Rules, 2021.
- Fact-checking initiatives and content takedown.
- Need for accountability without curbing free speech.



8 WAY FORWARD

- Strengthen digital literacy and critical thinking.
- Promote responsible social media use.
- Strict action against hate speech and fake news.
- Encourage dialogue, empathy and fact-based discourse.

